हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

2071

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 Dated Shimla-171002, 12-1-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.6431 ha of additional forest land in favour of M/s Ramesh Hydro Power Private Limited for construction of Road to weir site, dumping site/crusher plant and bridge from power house to intake site of the existing 24.00MW Selti-Marsang SHEP,within the jurisdiction of Kinnaur Forest Divison, Distt. Kinnaur, HP.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/ 01/53/2017/FC/1663 dated 10-01-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.6431** हैक्टेयर वन भूमि को **M/s Ramesh Hydro Power Pvt. Ltd.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा guideline para 3.2 (viii)(b) के अतंर्गत प्रस्ताव के अनुसार 322 वृक्षों का रोपण एवम् 07–10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी. वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

7 निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरांत जहां–जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाती के पौधों का रोपण किया जाएगा।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जाएगा।

9 Layout Plan भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।

10 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान / पातन नही किया जाएगा।

11 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection)Act,1986.

12 The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

13 The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Departmen. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumpin material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.

Contd./2

14 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc.

15 The renewal period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of mining lease granted in accordance with the Himachal Pradesh Minor Mineral (concession)Revised Rules, 1971, or project life, whichever is less.

16 The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

17 User agency shall submit the annual report on compliance to conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.

18 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Kinnaur, HP.

19 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2016** (FCA) Dated Shimla-171001 the, 12-1-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with a request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The CCF(FCA)-cum-Nodal Officer O/o HPFDHQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kinnaur Distt., Kinnaur Himachal Pradesh .
6. DFO Kinnaur Forest Division, Distt., Kinnaur, H.P.
8. M/s Ramesh Hydro Power Pvt. Ltd.,
9. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 12-1-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S/FCA
15/1
APCCF(FCA)